हिन्दी साप्ताहिक

हर्षिता टाइम्स

RNI Regn. No. UTTHIN/2008/28646

• वर्ष : 15 • अंक : 20 • देहरादून, • वृहस्पतिवार 08 जून, 2023 • मूल्य : 1 रुपये • वार्षिक : 50 रुपये • पृष्ट : 4

1550 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी : मुख्यमंत्री धामी

- *1425 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।*
- *सीएम धामी ने 55 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।*

देहरादून। 1425 अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड पुलिस में नियुक्ति दी गई है। पुलिस लाईन, देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। आरक्षी जनपद पुलिस, आरक्षी पी.ए.सी/आई.आर.बी तथा फायरमैन में चयनित कुल सभी 1425 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। मुख्यमंत्री ने कहा पुलिस आरक्षी के जो 1550 शेष रिक्त पद हैं, उन पर नई भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों एवं उनके माता-पिता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य के जनपदों एवं पीएसी वाहिनियों में पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों में पुलिस आरक्षी के रूप में हमारे ऊर्जा से भरे नवयुवक एवं नवयुवतियां पुलिस का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। पुलिस आरक्षी पुलिस फोर्स की प्राथमिक इकाई है, जो विभाग में नींव की तरह कार्य करते हैं एवं विभिन्न थाने चौकियों एवं चौराहों पर पुलिस का मुख्य चेहरा बनकर तैनात रहते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारे ये पुलिस आरक्षी कड़ी मेहनत, लगन एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि का एक आवश्यक अंग है। उत्तराखंड पुलिस हमेशा से अपने कार्य के प्रति समर्पित रही है और हर विपरीत परिस्थितियों में हमारी पुलिस फोर्स ने बेहतरीन कार्य किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड पुलिस को एक आधुनिक और स्मार्ट पुलिस बल बनाने के लिए

संकल्पबद्ध है। उत्तराखण्ड पुलिस ने मित्रता, सेवा एवं सुरक्षा के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई है। उत्तराखण्ड की आबादी के अलावा राज्य में राज्य की आबादी से लगभग पांच गुना श्रद्धालुगण देवभूमि आते हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारी मित्र पुलिस के जवान पूरी तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझकर सेवाभाव से अपनी ड्यूटी करते हैं। हम सही अर्थो में अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करने में सफल रहते हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में पूर्ण पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं कराने के लिए कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। इस कानून के लागू होने के बाद अभी तक सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से सकुशल संपन्न कराई जा चुकी हैं। इस कानून के प्रावधान इतने कड़े किये गए हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी नकल माफिया खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए उन्होंने तय किया कि इसके लिए चाहे कितने भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़े, लेकिन एक गरीब माता-पिता के बेटे एवं बेटी के साथ वे अन्याय नहीं होने देंगे।

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा उत्तराखण्ड पुलिस को 1425 नये जवान मिल गये हैं। सात साल बाद उत्तराखण्ड पुलिस को नये आरक्षी मिले हैं। समारोह में पर मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक विनोद चमोली, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पीआरडी विभाग की नियमावली में जून अंत तक आवश्यक संशोधन कर दिया जाएगा : रेखा आर्या

देहरादून : प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और प्रांतीय रक्षक दल के पदाधिकारियों के साथ पीआरडी एक्ट, नियमावली, पीआरडी जवानों से संबंधित पूर्व में हुई बैठकों के बिन्दुओं पर अनुपालन, पीआरडी से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणा तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों द्वारा पीआरडी विभाग की नियमावली के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें आवश्यक संशोधन करते हुए जल्द ही इसी माह इसका जिओ जारी कर दिया जाएगा।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी सरकार ने पीआरडी विभाग में तैनात गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश, जवानों को मानवीय, वित्तीय और शासकीय रूप से अनुमन्य सेवाओं की व्यवस्था, पीआरडी सेवकों को 60 वर्ष तक की नौकरी सहित पीआरडी एक्ट 1948 में संसोधन सहित कई अन्य व्यवस्थाएं की हैं, जिसका कि जल्द ही जिओ जारी किया जाएगा, निश्चित ही इन सभी सुविधाओं के लागू होने से हमारे

स्वयंसेवकों को भविष्य में लाभ प्राप्त होगा।

मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में अभी तब तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था और तब से यही एक्ट उत्तराखंड में चलता हुआ आ रहा था। कैबिनेट के माध्यम से एक्ट लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में संसोधित करते हुए उनके विभिन्न प्रकार के कार्य जिसमे टेक्निकल,चतुर्थ श्रेणी या अन्य विभागों में जहां उनकी आवश्यकता हो उन्हें वहां समायोजित किया जाएगा। वही गर्भवती महिलाओं को भी आने वाले समय मे मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। बताते चले कि धामी कैबिनेट में ही एक्ट पारित किया गया है।

इस अवसर पर बैठक में सचिव खेल एवं युवा कल्याण अभिनव कुमार, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण जितेंद्र सोनकर, संयुक्त निदेशक युवा कल्याण अजय अग्रवाल, उपनिदेशक शक्ति सिंह, डिप्टी डायरेक्टर सर्वेन्द्र जयराज, एडिशनल सेकेट्री निर्मल कुमार, दीप्ति जोशी, प्रांतीय रक्षक दल के अध्यक्ष प्रमोद मंद्रवाल सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

'विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस' पर मैक्स अस्पताल ने किया जागरूक

देहरादून : ब्रेन ट्यूमर तेजी से युवा और बूढ़े समान रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ये घातक और सौम्य हो सकते हैं। मैक्स अस्पताल की मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज के विशेषज्ञों ने 'विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस' पर जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया को संबोधित किया।

मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. (ब्रिगेडियर) एच.सी. पाठक, वीएसएम, डायरेक्टर- न्यूरोसर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल देहरादून ने कहा हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्य तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं जो घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। खोपड़ी के अंदर ऊतकों की असामान्य वृद्धि से 'ट्यूमर' का निर्माण होता है जो कि सामान्य ऊतकों को नष्ट करने और उन पर दबाव का कारण बनता है। लगातार सिरदर्द सहित लक्षणों की शुरुआती पहचान फायदेमंद हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे इलाज के नतीजे और मरीजों की रिकवरी में काफी सुधार होता है।

डॉ. ए.एम.ठाकुर, प्रिंसिपल कंसल्टेंट, न्यूरोसर्जरी ने कहा ये ट्यूमर घातक (कैंसर) या सौम्य (गैर-घातक) हो सकते हैं। घातक ब्रेन ट्यूमर, ज्यादातर, ब्रेन मैटर (आंतरिक) से उत्पन्न होते हैं

और इसे केवल समय की परिवर्तनशील अवधि के लिए नियंत्रित किया जा सकता है जिसके लिए उपलब्ध उपचारों के विभिन्न तौर-तरीकों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। दूसरी ओर, सौम्य ट्यूमर, ज्यादातर मस्तिष्क के आसपास की संरचनाओं से उत्पन्न होते हैं।

इस अवसर पर वीएसएम, डायरेक्टर- न्यूरोसर्जरी और डॉ संदीप सिंह तंवर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट- ऑपरेशंस एंड यूनिट हेड मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल देहरादून उपस्थित रहे।

शिक्षा विभाग और डीसी के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

देहरादून। शिक्षा विभाग और डेवलपमेंट कंसोर्टियम ने उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। एमओयू पर बंशीधर तिवारी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और अनामिका श्रीवास्तव, संस्थापक और सीईओ, डेवलपमेंट कंसोर्टियम द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

एमओयू के तहत डेवलपमेंट कंसोर्टियम उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर संस्थानों को मज़बूत बनाने, शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षकों को सक्षम बनाने और गुणवत्ता सामग्री की पहुंच को बढ़ाने के लिए डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मिलकर काम करेगा।

सम्पादकीय

मोटा अनाज वर्ष के माध्यम से नई पीढ़ी के लोग भी इन अनाजों का वैज्ञानिक आधार पर महत्व समझेंगे और स्वीकार करेंगें और जब स्वीकार करेंगे तब वह भी इस इनकी खेती और इनसे बने नये व्यंजनों को बनाकर स्टार्टअप्स व नवाचार भी कर सकेंगे। मोटा अनाज उपभोक्ता, उत्पादक व जलवायु तीनों के लिए अच्छा माना गया है। ये पौष्टिक होने के साथ कम पानी वाली सिंचाई से भी उगाए जा सकते हैं। विषेषज्ञों का मत है कि कुपोषण मुक्त और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिये मोटे अनाज की अहम भूमिका होगी और इसके लिए देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मोटे अनाज को प्रोत्साहन वर्तमान समय की मांग भी है क्योंकि यह अनाज आधुनिक जीवन शैली में बदलाव के कारण सामने आ रही कई बीमारियों व कुपोषण को रोकने में सक्षम है।

01 जनवरी 2023 से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष आरम्भ हो गया है। केंद्र सरकार ने मोटा अनाज वर्ष को सफल बनाने के लिए काफी समय पूर्व से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और अब यह सफलतापूर्वक धरातल पर उतरने को तत्पर हैं और किसानों को लाभ मिलने की बड़ी संभावना है। एक ओर इससे कुपोषण की समस्या से निपटने का नया और सरल मार्ग मिलेगा। एक समय था जब भारत की हर थाली में केवल ज्वार, बाजरा, रागी, चीना, कोदो, सांवा, कुटकी, कुटटू और चौलाई से बने हुए व्यंजन ही हुआ करते थे लेकिन फिर समय बदलता गया और आज स्थिति यह हो गयी है कि लोग इन अनाजों का महत्व तो दूर नाम भी भूल गए हैं। आज सभी सम्मेलनों में कृषि मंत्रालय व खाद्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के सहयोग से मोटे अनाजों से बने उत्पादों का ही प्रदर्शन किया जा रहा हैं व देश विदेश से आ रहे सभी अतिथियों को मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे जा रहे हैं जिससे इनका डंका विश्व भर में बजना तय हो गया है।

मोटा अनाज वर्ष में हम सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और अपने भोजन में इसको नियमित रूप से स्थान देना चाहिए क्योंकि इसमें कई विषेषताएं होती हैं। आज जब विश्व का बड़ा हिस्सा कुपोषण से लड़ रहा है सनातन भारत की मोटे अनाज वाली थाली समाधान के रूप में देखी जा रही है।

देश के 55 शहरों में जी 20 सम्मेलन होने हो रहे हैं। मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए इन अवसरों का भरपूर लाभ लिया जायेगा। आंगनबाड़ी और मध्यान्ह भोजन योजना में भी मोटे अनाजों को शामिल कर लिया गया है।

22 दिनों से लापता हिमांशु एम्स की मदद से घर वापस लौटा

ऋषिकेश। पिता के द्वारा प्रताड़ित किए जाने और रोज-रोज की डांट से क्षुब्ध होकर 14 साल का एक नाबालिग घर छोड़कर 250 किमी दूर भाग आया। इस दरम्यान दृष्टिबाधित इस मासूम के पैर की एड़ी में कील चुभ गई और इलाज के अभाव में जख्म गहरा हो गया। असहनीय दर्द झेल रहे इस बच्चे के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। किसी ने उसे एम्स पहुंचाया तो एम्स के चिकित्सकों व अन्य स्टाफ ने न केवल घर से भागे इस नाबालिग का निःशुल्क इलाज किया अपितु इसके घर सूचना भेजकर उसे माता-पिता के सुपुर्द कराने में विशेष भूमिका भी निभाई। अस्पताल से बच्चे को सकुशल घर लौटते वक्त परिजनों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। कहने लगे ''थैंक्यू एम्स''।

दिल्ली से हरिद्वार और हरिद्वार से एम्स अस्पताल ऋषिकेश तक के सफर की कहानी में 14 वर्षीय हिमांशु को जीवन की इस छोटी उम्र में पेश आए तमाम झंझावातों ने तोड़ कर रख दिया था। मानसिक वेदना और दिन-प्रतिदिन गहराते पैर के जख्म के कारण हिमांशु अवसादग्रस्त होने के कारण कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। बीते माह 28 मई को किसी ने इस नाबालिग को एम्स के गेट तक पहुंचाने में मदद की तो इसके पैर के घाव को देखकर सुरक्षा कर्मियों की मदद से इसे तत्काल एम्स की ट्रॉमा इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। एक आंख जन्म से ही दृष्टिबाधित होने के कारण परेशानी यह थी कि यह बच्चा न तो ढंग से देख पा रहा था और पकड़े जाने के डर से न ही खुलकर बोल पा रहा था।

आंखें बता रही थी कि वह अपनों से बिछुड़ गया है और कई दिनों से इधर-उधर भटकते रहने के कारण कुछ स्पष्ट बोलने की स्थिति में नहीं है।

इन हालातों में उसे अज्ञात पेशेंट के रूप में दर्ज कर उचित इलाज के लिए ट्रॉमा इमरजेंसी से पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही ट्रॉमा विभाग ने नाबालिग अज्ञात बच्चे के भर्ती होने की सूचना संस्थान के जनसंपर्क कार्यालय तक पहुंचाई। अस्वस्थता के कारण यह बच्चा गुमसुम था और किसी को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा था कि उसका घर कहां है और किन हालातों में वह एम्स तक पहुंचा है। इस पर विभागीय स्टाफ के माध्यम से विभिन्न स्तर से कई बार प्रयास किए गए। बच्चे से कई बार पूछने के बाद जब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया तो उसके कपड़े खंगाले गए। उसके कपड़ों से बरामद हुई एक पचह्न में एक फोन नम्बर पाया गया। इसी फोन नम्बर के आधार पर बच्चे के घर तक सूचना भेजी जा सकी। चिकित्सकों के अनुसार पैर में कील घुसने और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उसके घाव से मवाद बहने की स्थिति आ गई थी।

3 दिन तक अस्पताल में इलाज करने के बाद बीते रोज सूचना मिलने पर जब बच्चे के परिजन एम्स पहुंचे तो बच्चे को परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया गया है। एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉ. मीनू सिंह ने इसे लीक से हटकर किया गया एक रचनात्मक कार्य बताया। उन्होंने सेवाभाव से किए गए इस उत्कृष्ट कार्य के लिए संबन्धित स्टाफ की प्रशंसा की।

पहलवानों के खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है : दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर 'झूठे आरोप' लगाने और नफरती भाषण देने के लिए पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को यहां की एक अदालत में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की।

पुलिस ने अदालत से याचिका को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पहलवान नारे लगाते नहीं नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है। (भाषा)

केंद्रीय योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं : अजय

हल्द्वानी। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के नौ साल की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना सोशल मीडिया वॉलिटियर की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वॉलिटियर को केंद्रीय योजनाओं को घर-घर तक प्रचार-प्रसार करना है। इसके लिए उन्हें सरकार की हर योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, उज्जवला, सौभाग्य जनधन, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन जैसी महत्वकांक्षी योजनाओं से सभी को फायदा मिला है। कुमाऊं संभाग कार्यालय में सोशल मीडिया वॉलिटियर मीट में कहा कि मोदी सरकार ने अब तक हर वर्ग के लोगों तक केंद्र की योजनाओं का फायदा पहुंचाया है।

महासंपर्क अभियान के कुमाऊं संयोजक पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने वॉलिटियर्स को सोशल मीडिया के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर भ्रमण के दौरान भटहट के पिपरी में बन रहे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से जवाबदेही के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने पर निर्माण एजेंसी पर जुर्माना लगाने तथा इसके बाद भी सुधार न होने की दशा में एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने आयुष विश्वविद्यालय के ले-आउट का अवलोकन करने के साथ परिसर का भ्रमण कर अब तक हुए निर्माण

का जायजा लिया। उन्होंने एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल, जल-निकासी आदि कार्यों को सबसे पहले कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि कुलपति के साथ बैठक कर कार्यों की प्राथमिकता तय की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में तेजी लाने के लिए एक साथ 1200 से 1500 मजदूरों-कारीगरों को कार्य पर लगाया जाए।

आयुष विश्वविद्यालय के निरीक्षण के दौरान सीएम ने मानीराम-बालापार मार्ग पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ओवरब्रिज निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष किसानों को मुआवजा वितरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी का मुआवजा बाकी हो तो जल्द से जल्द उसे उपलब्ध करा दिया जाए।

देवभूमि के स्वरूप को बनाये रखने के किये जा रहे प्रयास : मुख्यमंत्री

ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित होटल में राज्य के समग्र विकास की दिशा में की जा रही पहल एवं इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों पर भी विचार रखे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश का समग्र विकास हमारी प्राथमिकता है। इसके लिये अधिकारियों को उत्तरदायित्व के साथ जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के निर्णयों को तत्परता से लागू करने के लिये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड धर्म आध्यात्म एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला प्रदेश है। इसके मूल स्वरूप को बनाये रखने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मातरण के रूप में किया जाने वाला कृत्य तथा सरकारी भूमि पर किया जाने वाला अतिक्रमण किसी भी दशा में सहन नहीं किया जायेगा। सरकारी भूमि पर किया जाने वाला अतिक्रमण हटाने के लिये अभियान जारी रहेगा। अब तक 2700 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्षो से पूर्व की वसावटों को छेड़ा नहीं जायेगा। प्रदेश में बिना किसी तुष्टिकरण के सबका साथ, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास से समान रूप से सभी को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हमारा एक एक पल प्रदेश के समग्र विकास के लिये समर्पित है। 2025 तक उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो इस दिशा में हमारे प्रयास जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास हेतु जो भी योजनायें स्वीकृत हुई हैं उन्हें पूर्णता की ओर ले जाने के लिये हम संकल्पबद्ध है। प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो इसके लिये भी हम प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जायेगा। राज्य में निवेश बढे, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि एवं औद्योगिक वातावरण सृजन हो इसके लिये लैण्ड बैंक तैयार कर सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है।राज्य का शान्त वातावरण उद्यमियों के सर्वथा अनुकूल है। हमारा यह भी हमारा प्रयास है। पर्यटन, उद्योग, कृषि आदि महत्वपूर्ण विभागों की नीति तैयार कर स्वरोजगार की योजनाओं को बढावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 09 सालों में उत्तराखण्ड राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को विभिन्न विकास योजनाएं दी गई है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से कार्य हो रहा है। ऋषिकेश को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने राज्य लीडर से अचीवर की श्रेणी में आये विकास के नवरत्नों पर पर बोलते हुए बताया कि किस तरह विकास के नवरत्न के तहत चल रहे कार्य उत्तराखंड के लिए आने वाले दिनों में कितने अहम साबित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जनता से जो वायदे किये हैं, उन्हें पूरा किया जायेगा। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद पहली ही कैबिनेट में समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिसका ड्राफ्ट 30 जून तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कमेटी की रिपोर्ट आने पर सभी विधि विशेषज्ञों एवं समाज के प्रबुद्धजनों से बात कर कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया जायेगा एवं शीघ्र लागू किये जाने की दिशा में कार्य किया जायेगा। उत्तराखण्ड देश में इस कानून को लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा।

उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून में 10 वर्ष की सजा तथा नकल माफिया की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है, नकल में सम्मिलित कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए हमने भारतवर्ष का सबसे सख्त कानून बनाया है जिसमें नकल कराने वाले व्यक्ति के लिए उम्र कैद तक का भी प्रावधान करने के साथ ही सारी सम्पत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जो अभ्यथह्न नकल करने में एक बार पकड़ा गया तो 03 साल तक अगर वह इसमें फिर से संलिप्त पाया जाता है तो अगले 10 वर्षो तक वह किसी परीक्षा में भाग नही ले सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल विरोधी कानून आने पर अब अभ्यर्थियों का चयन उनके योग्यता, प्रतिभा एवं क्षमता के आधार पर हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उड़ीसा के बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना में संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे समय में देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए तथा राजनीतिक पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद के लिये आगे आना चाहिये।

ओडिशा ट्रेन हादसा अब तक क्यों नहीं हो पाई 187 शवों की पहचान

ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुई भीषण रेल दुर्घटना में अब तक 275 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। रविवार सुबह तक मरने वालों की संख्या 288 बताई जा रही थी लेकिन अब ओडिशा के चीफ़ सेक्रेटरी प्रदीप जेना ने आंकड़ों में सुधार करते हुए मृतकों की संख्या 275 बताई है। हादसे में एक हज़ार के क़रीब लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कइयों की हालत गंभीर बताई गई है।

लेकिन एक अहम बात ये है कि त्रासदी में मरने वाले 275 लोगों में से अब तक 187 लोगों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। ऐसे में उन लोगों के परिजनों को मुआवज़ा कैसे मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हज़ार से अधिक घायलों को भुवनेश्वर से लेकर बालासोर, भद्रक और कटक के अस्पतालों में रखा गया जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने लोगों को मुआवज़े देने की ज़िम्मेदारी ली है, और इसलिए लिए हेल्प डेस्क भी चालू किया गया है।

चीफ़ सेक्रेटरी का कहना है कि 170 शवों को राजधानी भुवनेश्वर द्धएम्स और दूसरे अस्पतालों मेंऋ शिफ्ट किया गया है। बाकी 17 शवों को भी भुवनेश्वर ले जाया जा रहा है। मृतकों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए एंबुलेंस में दो शव रखकर यानी कुल शवों को 85 एंबुलेंस की मदद से भुवनेश्वर शिफ्ट किया गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसमें घटनास्थल पर मौजूद लोग शवों को बहुत असम्मानजनक तरीके से गाड़ियों में रख रहे थे

शवों की शिनाख्त कैसे होगी ?

पीड़ित परिवारों की मदद के लिए भुवनेश्वर के सत्य नगर स्थित भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है।

शवों की शिनाख्त के लिए राज्य सरकार ने एक लिस्ट बनाई है जिसे तस्वीरों के साथ तीन वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है। चीफ़ सेक्रेटरी ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर शवों की डीएनए परीक्षा भी की जाएगी। शवों की शिनाख्त करने के लिए प्रशासन ने परिजनों से भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से संपर्क करने के लिए कहा है। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।

टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर पीड़ित परिवार दुर्घटना से प्रभावित अपने लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी जानकारी भी इन तीन वेबसाइटों पर अपलोड की गई है। हालांकि अस्पताल के अनुसार लिस्ट अभी नहीं बन पाई है।

शवों को भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल, कैपिटल अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों में रखा गया है। भुवनेश्वर के म्युनिसिपल कमिश्नर विजय अमृत कुलांगे ने बीबीसी को बताया कि मृतकों के परिजन को हर तरह की सहायता देने की व्यवस्था की गई है। लोगों को शव की तलाश में भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहचान के बाद परिजन शव को अपने इलाक़े में ले जा सकें इसके लिए ओडिशा सरकार ने निःशुल्क व्यवस्था भी की है। हालांकि इससे पहले शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

पीएमओ ने प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की। (बीबीसी)

अमर्यादित कपड़ो पर मंदिर में प्रवेश नहीं

हरिद्वार। कांवड़ मेला शुरू होने से पहले ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर और पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। हाफ पैंट, फटी जींस, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट पहनकर आने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मर्यादित कपड़े पहनकर आने वालों को ही मंदिर में प्रवेश कर दर्शन करने की अनुमति होगी।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कुछ दिन पहले इन दोनों मंदिरों में अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मंदिरों में मर्यादा को बनाए रखने के लिए कपड़ों की मर्यादा जरूरी है। दोनों मंदिरों में ड्रेस कोड को लागू करते हुए बैनर लगा दिए गए हैं। महिला हो या पुरुष अब अमर्यादित कपड़ों में इन मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने कहा कि शालीनतापूवर्क व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के शरीर 80 फीसदी तक ढके होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश मंदिर चाहे वह संतों के हो या फिर अन्य कमेटी, सरकार के ट्रस्ट के अधीन हो सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है। बताया कि दक्षिण भारत के कई मंदिरों में ड्रेस कोड पहले से लागू है। उत्तराखंड तीर्थो का प्रदेश है यहां भी इसकी जरूरत थी।

प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिले खेल मंत्री ठाकुर बृजभूषण के खिलाफ आरोप पत्र 15 जून तक

नयी दिल्ली (भाषा)। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ छह घंटे तक चली मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून तक आरोपपत्र दाखिल हो जाएगा और पहलवानों ने भी तब तक अपना प्रदर्शन स्थगित करने पर सहमति जताई है।

मामले में एक नाबालिग समेत सात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 23 अप्रैल से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को खेल मंत्री ठाकुर ने मुलाकात के लिए बुलाया था। इस बैठक में सरकार ने पहलवानों की अधिकतर मांगों पर सहमति जताई है।

चुनिंदा 50 चिकित्सा संस्थानों में एम्स ऋषिकेश ने 22 वां स्थान प्राप्त किया

ऋषिकेश। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा देश के सर्वोच्च 50 चिकित्सा संस्थानों की सूची सोमवार को जारी कर दी गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स ऋषिकेश ने इस बार देश के चुनिंदा 50 चिकित्सा संस्थानों में 22 वां स्थान प्राप्त किया है। पिछली बार एम्स ऋषिकेश 49वें नंबर पर था। संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉ. मीनू सिंह ने इसे टीम वर्क से की गई मेहनत का प्रतिफल बताया है।

शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 की सूची जारी की। उत्कृष्ट मेडिकल कॉलेजों की सूची में एम्स ऋषिकेश ने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार बढ़त हासिल कर 60.06 स्कोर के साथ 22वां स्थान हासिल किया है।

एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक ने इसे संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि भविष्य में टीम वर्क के साथ ऑल इंडिया रैंकिंग में और बेहतर प्रदर्शन कर सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकें।

संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपलियाल ने बताया कि रैंकिंग में इन सभी चिकित्सा संस्थानों के स्नातक और परास्नातक प्रोग्राम, स्टूडेंट स्ट्रेंथ प्रोग्राम, प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज प्रोग्राम के मानकों को परखा जाता है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ राजेश कुमार ने नैनीताल जिला अस्पताल का किया निरीक्षण

नैनीताल। ट्रेनिंग से वापस आते हैं एक बार फिर पहले की तरह स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। विगत एक माह से स्वास्थ्य सचिव मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षणरथ थे। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद ज्वाइन करते ही स्वास्थ्य सचिव ने ग्राउंड जीरो पर व्यस्थाओं को परखना शुरु कर दिया है। बिना समय गवाएं स्वास्थ्य सचिव कुमाऊ दौरे पर निकल गये। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने नैनीताल जनपद के जिला अस्पताल बीडी पांडे का निरीक्षण किया।

मंगलवार को उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव डॉ. राजेश कुमार ने जिला अस्पताल बीडी पांडे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल वार्ड, जिरियाट्रिक वार्ड, ऑर्थो वार्ड, आइसीईयू, चिल्ड्रन वार्ड समेत अन्य वार्डो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ़ सफाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की, स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल में सीएमओ को सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, साथ ही वार्डो के बेडों व बेडशीट्स को बदलने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव डॉ. राजेश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा आपातकालीन केस आने पर डॉक्टर उपस्थित रहे।

इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल भी जाना और मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं व सुविधाओं को लेकर जानकारी प्राप्त की जिस पर उन्हें कोई शिकायत नही मिली। वही पीएमएस से डॉक्टरों की जानकारी ली गई लेकिन पीएमएस को डॉक्टरों की जानकारी न होने पर भी स्वास्थ्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में खराब स्वास्थ्य उपकरण हटाकर नए उपकरण लाने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने हेल्थ एटीएम को जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए, ताकि अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सकें। साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यदि अस्पताल आने वाले मरीजों द्वारा कोई शिकायत मिली या मरीजों के साथ लापरवाही की हुई बर्दाश्त नही की जाएगी।

इस दौरान डायरेक्टर तारा आर्य, सीएमओ भागीरथी जोशी, पीएमएस डॉ. एलएमएस रावत, डॉ. अनिरुद्ध गंगोला, डॉ.एमएस रावत, वार्डन शशिकला पांडे, कुंदन बिष्ट समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

देहरादून में स्पा सेन्टर में अनैतिक देह व्यापार का खुलासा

देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य महिला आयोग ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की टीम के साथ पटेल नगर क्षेत्र में स्थित स्पा सेंटरों में छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट का खुलासा किया है।

महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल के सम्पर्क में ह्यूमेन राइट काउंसिल एनजीओ के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी से पता लगा की पटेलनगर के स्पा सेंटर में अनैतिक देह व्यापार के चलने की संभावना है। जानकारी मिलते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने छापेमारी के लिए टीम को सूचना दी और मौके पर निरीक्षण के लिए साथ गई। जिसमे की बॉडी रिलेक्स स्पा, मैजिक टच स्पा व पीसफुल स्पा सेंटरों में मसाज देने के नाम पर देह व्यापार का रैकेट चल रहा था। जिसका खुलासा महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ आयी टीम द्वारा किया गया है।

वहीं मौके इन स्पा सेंटरों में से 13 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। जो कि भिन्न भिन्न शहरों से है। जानकारी मिली है की गिरफ्तार की हुई 13 लड़कियों में से 1 नेपाल, से 1 सिक्किम से, 1 सिलीगुड़ी, 2 टिहरी से 1 अल्मोड़ा से 1 हरिद्वार व 1 देहरादून से है। इन लड़कियों के पास स्पा या फिजियोथेरेपी का कोई भी प्रशिक्षण या प्रमाणपत्र नही पाया गया है। एक स्पा सेंटर में से अनैतिक वस्तुंए भी पाई गई है जिन्हें पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। फिलहाल लड़कियां पुलिस की हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

निरीक्षण टीम ने स्पा सेंटर में मौजूद दस्तावेजों व वहां से बरामद हुए समान को भी जब्त किया गया है।

सीएम ने क्रिकेटर मधवाल को किया सम्मानित

इेहरादून। उत्तराखंड के क्रिकेटर आकाश मधवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उत्तराखण्ड के क्रिकेटर आकाश मधवाल ने आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हुए गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड एथलेटिक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जितेन्द्र नेगी एवं संजय सिंह भी उपस्थित थे।

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनें लीगल सेल : उमाकांत लखेड़ा

देहरादून। उत्तरांचल प्रेस क्लब में सोमवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। पत्रकारों से संवाद करते हुए लखेड़ा ने कहा कि हमारा अस्तित्व अपनी माटी से है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए लीगल सेल का गठन पूरे देश में प्रेस क्लबों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके तहत सभी पत्रकारों को कानूनी मदद के लिए वकीलों का पैनल तैयार करना चाहिए। कई वकील ऐसे है जो पत्रकारों के मुकदमें निरूशुल्क लड़ते है। उन्होंने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रेस क्लब परिसर में पौध रोपण भी किया गया।

सोमवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ संवाद में श्री लखेड़ा ने कहा कि पत्रकारिता में हर दौर में चुनौतियां आती हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, कुचले वर्ग के साथ खड़े होना ही पत्रकारिता है। उन्होंने कहा कि पहले मीडिया खबरों को फिल्टर करता था लेकिन अब फेक न्यूज को अहमियत देता है। जो भी खबर लिखे उस पर रिसर्च जरूर करें। आज मीडिया की आजादी खत्म हो रही है। पत्रकारिता आज से 30 साल पहले खबरों की फैक्ट्री नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी बदल गयी है अभी आगे और रिफाइंड टेक्नोलॉजी आयेगी। आने वाला समय एआई का आ रहा है जो कि फायदेमंद भी है और नुकसानदेय भी है और यह हमारा चुनाव होगा। हमारा हिंदी पत्रकारिता में रिसर्च कमजोर है। रिसर्च और नए प्रयोगों को पत्रकारिता में इस्तेमाल करके ही हम विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय राणा और संचालन क्लब महामंत्री विकास गुसाई ने किया। इस अवसर पर क्लब वरिष्ठ उपाध्यक्ष रश्मि खत्री, कनिष्ठ उपाध्यक्ष दरवान सिंह, कोषाध्यक्ष मनीष चंद्र भट्ट, संयुक्त मंत्री राजीव थपलियाल, मीना नेगी, सम्प्रेक्षक मनोज सिंह जयाड़ा, कार्यकारिणी सदस्य मंगेश कुमार, विनोद पुंडीर, पूर्व अध्यक्ष दर्शन सिंह रावत, जितेंद्र अंथवाल, पूर्व महामंत्री गिरिधर शर्मा के साथ ही क्लब सदस्य आरपी नैनवाल, नीरज कोहली, कुंवर बहादुर अस्थाना आदि मौजूद थे।

नदी में डूबा किशोर के शव को एसडीआरएफ ने किया बरामद

कालसी। थाना कालसी द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि एक किशोर साकिर पुत्र वहीद हसन उम्र 15 वर्ष निवासी भुड्डी, देहरादून, लालढांग टोंस नदी में नहाते समय गहरे पानी मे जाने से डूब गया है। सूचना मिलते ही पोस्ट मुख्य आरक्षी आशिक अली द्वारा टोंस

डाकपत्थर से एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम मय आवश्यक उपकरणों के घटनास्थल के लिए रवाना हुई। रेस्क्यू टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर अनेक संभावित स्थानों पर डीप डाइविंग करते हुए गहन सर्चिंग की गई परन्तु किशोर का कुछ पता नही चल पाया।

04 जून रविवार को पुन: एसडीआरएफ टीम द्वारा गहन सर्च अश्वपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ टीम के डीप डाइवर नदी में घटनास्थल के आसपास के स्थानों पर डीप डाइविंग के माध्यम से गहन सर्चिंग करते हुए किशोर साकिर के शव को नदी की गहराई से ढूंढ निकाला व सिविल पुलिस के सुपर्द किया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, सुबोध भट्ट द्वारा दून वाणी प्रिंटर्स डी0एल0 रोड, देहरादून से मुद्रित एवं मोहकमपुर कलां, माजरी मी, पो0ओ0 नवादा, देरादून, उत्तराखंड से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुबोध भट्ट मो0 9837383994, email : subodhbhatt09@gmail.com